

आवास की भारी कमी

मेडिकल कॉलेज में प्रति वर्ष 100 सीटों के हिसाब से 500 सीट का हॉस्टल होना जरूरी था जबकि बनाया गया मात्र 376 सीट वाला। दो साल पहले मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ा कर 125 और उसके बाद 150 दी गई। जाहिर है इससे आवास की समस्या बढ़ गई। इतना ही नहीं पीजी के भी 300 छात्र होने जा रहे हैं।

ऐसे में ईएसआई मुख्यालय में बैठे नालायक व हरामखोर अफसरों ने नये आवास बनाने की बजाय दस किमी दूर एनएचपीसी से किराये पर फ्लैट ले कर छात्रों को वहाँ ठहरा रखा है। इसके लिये करीब 12 लाख मासिक किराया, करीब साढ़े पांच लाख मासिक बस किराया तथा दो लाख मासिक बिजली बिल अदा करना पड़ रहा है। इस खर्च के साथ-साथ वहाँ सुरक्षा आदि पर जो खर्च होता है वो अलग से। छात्रों के आने जाने में जो समय बर्बाद होता है उसके तो कोई कीमत नहीं लगा सकता। आवास की यह समस्या प्रति वर्ष अधिक बढ़ती जाने वाली है।

छात्रों के अलावा ऐसार व जेआर तथा प्रशासनिक स्टाफ का भी परिसर में रहना अतिआवश्यक है। मौजूदा समस्या का देखते हुए अधिकांश स्टाफ परिसर से दूरदराज रहने को मजबूर है जिससे न केवल कारपोरेशन को अधिक खर्च करना पड़ रहा है बल्कि सेवाओं में भी बाधा पड़ती है। यदि मुख्यालय में बैठे इन अफसरों को थोड़ी सी भी समझ व चिंता होती तो समस्या के आने से पहले ही उसके निदान के लिए उचित कदम उठाए गए होते। परंतु दुख की बात तो यह है कि अभी तक भी इस दिशा में किसी का कोई ध्यान नहीं है। हालात की गंभीरता को देखते हुए तथा दूरगामी दृष्टि के अनुसार आसपास पड़ी जमीन में से दस एकड़ जमीन इस संस्थान को दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मजदूर मोर्चा- खाता संख्या-
451102010004150
IFSC Code :
UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

paytm

MM

Majdoor Morcha
UPI ID: 8851091460@paytm
8851091460

Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.

घर बैठे प्राप्त करें मजदूर मोर्चा
आज ही अपने हाँकर से कहें, कोई दिक्षित हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्किंगड़ के पाठक अरोड़ा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

- प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
- रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
- एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
- जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
- मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
- सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होड़ल - 9991742421

ईएसआई मेडिकल कॉलेज अस्पताल...

पेज एक का शेष है। इसके द्वारा 2000 से अधिक हव्य रोगियों का सफल इलाज किया जा चुका है। इसमें एंजिओग्राफी, एंजिओ प्लास्टी तथा हव्य के वॉल्ट्व बदलने तक के काम हो चुके हैं। इसके बावजूद अभी तक केन्द्रीय श्रममंत्री के मातहत काम करने वाले मुख्यालय ने न तो कोई टेक्नीशियन उपलब्ध कराये हैं और न ही आवश्यक पैरामेडिकल स्टाफ।

पैदाइशी गूंगे-बहरे बच्चे जो इलाज के अभाव में सदा के लिये गूंगे बहरे रह जाया करते थे, उनका भी यहाँ सफल इलाज होने लगा है। इस अस्पताल में अब तक ऐसे करीब 35 बच्चों का सफल इलाज किया जा चुका है। इसमें कॉक्लीयर नामक एक महीन सा यंत्र छोटे बच्चे के कान में शल्य चिकित्सा द्वारा फिट किया जाता है जिससे बच्चा सुनने लगता है और जब

मंत्रियों की पिकनिक पर कर्मचारियों की छुट्टी कुर्बान

छुट्टी के दिन दो केंद्रीय मंत्री पिकनिक मनाने मेडिकल कॉलेज में आ धमके लेकिन समाह में एक दिन छुट्टी पाने वाले तमाम कर्मचारियों को काम पर आने का आदेश दिया गया। इस ज्ञावरदस्ती की हाजिरी के बदल न तो बदले की छुट्टी दी जा रही है और न ही उस दिन की दिहाड़ी।

कुछ कर्मचारियों द्वारा इस बाबत मजदूर मोर्चा से शिकायत करने पर इस संवाददाता ने डीन से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उन्हें इसके एवज में बदले की छुट्टी अथवा वेतन दिया जाएगा।

मंत्री कृष्णपाल गूजर को सेक्टर आठ का ईएसआई अस्पताल व डिस्पेंसरियां क्यों नज़र नहीं आतीं?



मंत्री कृष्णपाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के उस विस्तार की मांग तो करने पहुंच गये जो कि पहले से ही तय हो चुका था, अपने क्षेत्र के सेक्टर आठ स्थित उस ईएसआई अस्पताल तथा उससे जुड़ी 14 डिस्पेंसरियों को सुचारू करने की मांग क्यों नहीं करते? विदित है कि ईएसआई के कार्पोरेशन के पैसे से हरियाणा सरकार द्वारा चलाये जाने वाले इस अस्पताल व डिस्पेंसरियों की हालत बेहद खस्ता है। अस्पताल की 200 बेड वाली बिलिंग में मात्र 15-20 पेशेंट ही दाखिल रहते हैं क्योंकि न तो यहाँ पर्याप्त डॉक्टर व स्टाफ हैं और न ही आवश्यक उपकरण व दवाएं, हर छोटे मोटे रोग के लिये मरीजों को रेफर कर दिया जाता है।

इस अस्पताल से जुड़ी 14 डिस्पेंसरियों की हालत तो और भी भयंकर है। अबल तो पूरा स्टाफ ही नहीं है और जो हैं भी वह भी काम करके राजी नहीं हैं। डॉक्टर सहेबान देर से आते हैं और जल्दी भाग लेते हैं। और तो और इनमें टीका लगाने व पट्टी बांधने तक की भी सुविधा नहीं है। जब इस तरह के छोटे-मोटे कामों के लिये भी मरीजों को मेडिकल कॉलेज आना पड़ेगा तो वहाँ की ओपीडी साढ़े चार हजार प्रति दिन होना स्वाभाविक है।

यदि मंत्री कृष्णपाल को अपने प्राप्टी डीलिंग के धंधे से थोड़ी-बहुत फुर्सत भी होती तो लाखों लोगों के लिये बनी इन डिस्पेंसरियों व सेक्टर आठ के अस्पताल की ओर थोड़ा सा ध्यान दे लेते। समझ नहीं आता कि प्रति माह जिले के अधिकारियों के साथ होने वाली मासिक बैठक में वे करते क्या हैं? क्या वे पूछ नहीं सकते कि डबल इंजन की सरकार द्वारा चलाये जा रहे ईएसआई के इस अस्पताल व डिस्पेंसरियों की दुर्दशा इतनी भयंकर क्यों हैं?

सुनने लगता है तो वह बोलने भी लगता है। इस उपकरण की कीमत करीब पांच लाख रुपये तथा सर्जरी का खर्च (व्यापारिक अस्पतालों में) पांच लाख से भी अधिक आता है।

सरकारी अस्पतालों में यह सुविधा न होने के चलते और ईएसआई कार्पोरेशन अपना खर्च बचाने के लिये ऐसे मरीजों को घुमा-फिरा कर भगाती रही है।

अस्पताल में तेजी से बढ़ते कार्यभार तथा स्टाफ की भारी कमी के साथ-साथ स्थानाभाव की ओर बार-बार मुख्यालय का ध्यान आकृष्ट करने के बावजूद जब किसी के कान पर जूँ तक नहीं रँगी तो संस्थान के डीन डॉ. असीम दास ने अपने इस्टीफे का नोटिस दे दिया था। बताया जाता है कि मसले की गम्भीरता को समझते हुए दुरस्त आये, आ तो गये। परन्तु अब सबाल यह है कि यह नई इमारत कब तक बन कर तैयार हो जायेगी? करने की नीयत हो तो यह काम एक साल से अधिक का नहीं है। और नीयत खारब हो तो मंज़ावली पुल की तरह दस साल में भी न हो।

जब विधायक सीमा त्रिखा मेडिकल कॉलेज के विरोध में धरने पर बैठ गई थी



बहुत कम लोगों को ज्ञान होगा कि 24 फरवरी 2009 तक इस मेडिकल कॉलेज के बनने की कोई सम्भावना नहीं थी। ईएसआई कार्पोरेशन ने स्पष्ट कह दिया था कि 15 एकड़ में बने एनएच तीन के 200 बिस्तर वाले इस अस्पताल को मेडिकल कॉलेज बने। इसका पहला कारण तो यह था कि मेडिकल कॉलेज का श्रेय एसी चौधरी को जा रहा था। और दूसरा बहाना ये था कि राहुल कॉलेजी की 10-20 द्विग्रामीय इस भूखंड में पड़ती थीं। सीमा त्रिखा इसे अपना बोट बैंक मान कर चल रही थीं इसलिये उन्हें खुश करने के लिये धरने पर बैठ गईं। कुछ दिन बाद निर्माण कम्पनी के टेकेदार ने उन द्विग्रामीयों के साथ बात-चीत करके उनके के लिये नाली व सड़क की व्यवस्था ठीक करके उन्हें राजी कर लिया। जिसके चलते वे तमाम द्विग्रामीयों उठकर नाली व सड़क के पार चली गईं।

इस संस्थान का संकट यहीं नहीं खत्म हुआ। एक के बाद एक रुकावट इसकी राह में खड़ी की जाती रही। हरामखोर पर तुले मुख्यालय के अधिकारी कभी नहीं चाहते थे कि यह मेडिकल कॉलेज बने। जैसे-तैसे इमारत भले ही बन कर खड़ी हो गई लेकिन इसके विरोधियों ने हथियार नहीं डाले। कभी इसे हरियाणा सरकार को सौंपने तो कभी किसी पूंजीपति के सौंपने के बाद यह रहे। भाय से 2015 में ईएसआई के तत्कालीन डीजी राजकुमार ने भाग-दौड़ करके